186

प्रेस संक्षिप्त

5वीं राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार समिति (एसएएबी), बिहार की दूसरी बैठक 29 जुलाई, 2022 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता श्री रामावतार शर्मा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना ने की और इसमें निम्नलिखित मनोनीत मानद बाह्य सदस्यों ने भाग लिया:-

1. प्रो. गोपाल कृष्ण पाल, कार्यकारी निदेशक, एम्स, पटना;
2. प्रो. सुनैना सिंह, कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर, बिहार
3. डॉ. अशोक कुमार घोष, अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
4. श्री राजेश झा, (भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक, स्वास्थ्य नीति केंद्र, एडीआरआई, पटना) (ऑनलाइन);
5. श्री समीर झा, प्रमुख शिक्षा आगा खान फाउंडेशन, पटना;
6. प्रो. डी.एम. दिवाकर, माननीय निदेशक एवं अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, विकास अनुसंधान संस्थान, जलसेन;
7. सुश्री अख्तरी बेगम, सचिव, इज़ाद (एनजीओ), बिहार, पटना।

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालय के निम्नलिखित वरिष्ठ अधिकारी/पदेन सदस्य, एस.ए.ए.बी. पटना ने भी बैठक में भाग लिया:-

1. श्री प्रवीण कुमार सिंह, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार;
2. श्री आदर्श अग्रवाल, उप महालेखाकार (प्रशासन और एएमजी-I और एएमजी-IV)
3. सुश्री पुष्पलता, उप महालेखाकार (एएमजी-II) - सह-पदेन सदस्य-सह-सचिव/एस.ए.ए.बी बिहार;
4. श्री शिव शंकर, उप महालेखाकार (एएमजी-III और V)

इस बोर्ड का उद्देश्य लेखा परीक्षा कार्यालय के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच पेशेवर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह ऑडिट से संबंधित मामलों पर सुझाव प्रदान करता है, जिसमें ऑडिट के कवरेज, दायरे और प्राथमिकता के साथ-साथ ऑडिट दृष्टिकोण और तकनीकों के बारे में सुझाव शामिल हैं।

बैठक में सदस्यों के बीच वर्तमान लेखापरीक्षा योजना के कार्यान्वयन के साथ-साथ लेखापरीक्षा के लिए वर्तमान में किए जा रहे विषयों से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, एसएएबी के सदस्यों ने आगामी लेखापरीक्षा योजना के लिए संभावित विषयों पर अपने सुझाव दिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यकों के लिए पूर्व एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और कुछ अन्य विषयों पर राज्य में लागू की जा रही विभिन्न योजनाओं पर गहन विचार-विमर्श किया गया। पीएचईडी के तहत नीर निर्मल परियोजना, एलएईओ द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन, फसल सहायता योजना, व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली आदि। चर्चा के दौरान, श्री घोष ने जोर देकर कहा कि नल के माध्यम से आपूर्ति किए जाने वाले पीने योग्य पानी की गुणवत्ता की जांच की जानी चाहिए। निदेशक, एम्स ने चर्चा की गई योजनाओं के लिए अपनाई गई निगरानी प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा करने का सुझाव दिया। प्रो. सुनैना सिंह ने ठोस कचरे के लिए अपनाई गई रीसाइक्लिंग प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। प्रो. डी.एम. दिवाकर ने नीर निर्मल परियोजना के सामाजिक अंकेक्षण की इच्छा व्यक्त की और यह जांच करने का सुझाव दिया कि बजट राशि से लाभार्थियों को कितना लाभ प्रदान किया गया है। सुश्री अख्तरी बेगम ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए लागू की गई योजनाओं की जांच करने का सुझाव दिया। श्री समीर झा ने यह आकलन करने का विचार दिया कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्षमता निर्माण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। श्री राजेश झा ने आरोग्य केंद्रों की प्रभावशीलता पर बल दिया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

उप महालेखाकार
-सह-पदेन सचिव,
राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड, बिहार।